SHRI DHAMANKAR: The work of the forest cooperative societies is being replaced by the State Corprations. Is it the policy of the Govment to do so?

SHRI T. A. PAI: I do not think it is the policy of the Government to replace the wood work done by cooperative societies. Rather the State Corporations would make the best use of the Forest Cooperative Societies in the States in the matter of exploitation of forest.

Haryana's request for more A.I.R. Stations

*570. SHRI RAM PRAKASH: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether State Government of Haryana have approached the Union Government for approval of more All India Radio Stations in the State, and

(b) if so, the broad outlines thereof and the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA): (a) No Sir.

(b) Does not arise However, a radio station has been set up at Rohtak and will be commissioned shortly.

श्री राम प्रकाश : आप ने अभी फरमाया कि रोहतक में रेडियो स्टेशन जल्दी चालू हो जाएगा । मैं जानना चाहता हूं कि इसमें कितना खर्चा लगेगा ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : इसका विधिवत् उद्घाटन अगले महीने की आठ तारीख को हो रहा है ।

श्री राम प्रकाश : क्या सरकार देहाती प्रोग्राम का टाइम बढ़ाने के लिये और हरियाणा के लिए टेलिविजन सेन्टर खोलने के लिये विचार कर रही है । आप जानते हैं कि हमारी प्रधान मंत्री जी का बीस सूत्री कार्यक्रम वहां बहुत तेजी से चल रहा है, साथ ही हमारे नौजवान लीडर श्री संजय गांधी समाजवाद के काम में बहुत इफेक्टिव साबित हुये हैं, इसलिये अगर सरकार देहाती प्रोग्राम का टाइम बढ़ा दे और वहां शीघ्र टेलिविजन सेन्टर खोलने की व्यवस्था कर दे तो इससे हमारे देहाती भाई बहुत लाभ उठा सकते है । क्या सरकार इस पर विचार कर रही है ?

श्री विद्या चरण शुक्ल इस बात पर विचार हो रहा है कि दिल्ली के टेलिविजन केन्द्र का कोई रिले स्टेशन वहां बनाया जाय, ताकि हरियाणा का बहुत बड़ा भाग उसके अन्तर्गत आ सकें । अभी यह प्रश्न विचाराधीन है, जब हमारे साधन इस लायक होंगे कि हम इस काम में लग सकें, तब हम काम को अपने हाथ में लेंगे ।

वर्ष 1976-77 के लिए बिहार द्वारा प्रस्तुत की गई पूरक योजना

*572. **श्री चिरंजीव झा :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिये 37 करोड़ रुपये की एक पूरक योजना केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की है, और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING (SHRI SANKAR GHOSE): (a) and (b). Yes, Sir. The proposals of the Government of Bihar involving an additional outlay of Rs. 37 crores are presently under consideration in the Planning Commission.

श्री चिरंजीव झा : श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से योजना मंत्री जी से जानना चाहता हूं—क्या विचार के समय इस मुद्दे पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा कि कुछेक विगत वर्षों मे गैर-जिम्मेदार तत्वों द्वारा पैदा किया गया अराजकता का वातावरण, घेराव, हड़ताल, तालाबन्दियां, आदि राज्य मे उत्पादन घटा रहे थे, जिसके कारण ही राज्य अपनी ओर से पर्याप्त साधन जुटाने में समर्थ रहा, एवं बिहार की आबादी के 74 प्रतिशत से भी अधिक लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं ?

मेरा दूसरा प्रश्न है—क्या योजना आयोग को पता है कि 37 करोड की इस पूरक योजना का मुख्य भाग 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम मे सम्बद्ध है, जिसमें आधारभूत आवश्यकता विद्युत्, सिंचाई, लघु उद्योग, ग्रामीण-पेय जल की आपूर्तियों के साथ-साथ पंचायतो मे लघु निर्माण के हेतु साधन उपलब्ध कराना है ?

MR. SPEAKER: Could you follow the question, Mr. Ghose?

SHRI SANKAR GHOSE: I have followed the question. We appreciate the problems of Bihar. So far as Bihar is concerned, the Plan-size in 1975-76 was Rs. 205 crores and during the current year, 1976-77 it will be increased to Rs. 242 crores; and the Central Plan assistance will also be increased by Rs. 6.87 crores and market borrowings will be increased by Rs. 2.46 crores.

श्री विभूति मिश्र: अध्यक्ष जी, प्रधान मंत्री जी यहां बैठी हुई हैं—चिरंजीव झा जी ने जैसा कहा है—बिहार में पिछले दिनों जो घटनायें घटी, जो हंगामें और दिक्कतें पैदा हुई, उनका मुकाबला करने के लिये बिहार सरकार को काफी रुपया खर्च करना पड़ा। इसके अलावा पिछले साल बाढ़ के समय, इस बात का क्रेडिट प्रधान मंत्री जी को है, उन्होंने खुद वहां जाकर पटना और सारे बिहार की देखभाल कर के वहां काम प्रारम्भ कराया। बिहार सरकार की इसमें जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति के लिये उन्होंने 37 करोड रुपया मांगा थी। बिहार की क्षति और बिहार का पिछड़ापन दोनों बातो को दृष्टि मे रखते हुये हमारे मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, वह सन्तोषप्रद नहीं है। बिहार की हालत को देखते हुये, क्या वे ऐसा महसूस करते हैं कि बिहार को रुपया ज्यादा बढाकर दिया जाये। यदि हां, तो वे कितने हद तक बढाने को तैयार हैं ?

SHRI SANKAR GHOSE: As I have already said, we are sympathetic to the problems of Bihar and we are trying to increase the allocation. It has been possible to increase it to Rs. 242 crores. We will always examine the situation and do the needful.

श्री रामावतार शास्त्री : अध्यक्ष जी, बिहार की आर्थिक स्थिति कितनी दयनीय है, आप भली भांति जानते हैं। इस बात को दृष्टि में रखते हुये मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि बिहार सरकार ने जो 37 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि की मांग की है, वह किन कामों के लिये है। उन्होंने जरूर उसको ब्यौरे भेजा होगा कि अमुक कामों के लिये उनको यह धनराशि चाहिये। मैं

जानना चाहता हूं कि यह ब्यौरा क्या है। क्या उन ब्यौरों के बारे में आपको क्या कहना है ? वे उचित हैं या नहीं अगर उचित हैं तो सरकार उनके बारे में क्या करना चाहती है ?

SHRI SANKAR GHOSE: If the hon. Member wants the break-up of Rs. 37 crores I have got it here. . .

MR. SPEAKER: He can give the broad heads.

SHRI SANKAR GHOSE: The broad heads are: Local Development Works of Panchayats Rs. 11 crores, power Rs. 10 crores, roads Rs. 4 crores and so on. There are a number of small miscellaneous items.

श्री ईश्वर चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह तो कोई जवाब नहीं आया ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि वे सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रहे हैं ।

तमिलनाडु में पुलिस संगठन

.576. श्री कमला मिश्र "मधुकर" . क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु के पुलिस संगठन में भारी परिवर्तन किये गये हैं जिससे बहुत से उच्चतर पुलिस अधिकारी भी प्रभावित हुये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या आरोप हैं और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किये जाने के बाद पुलिस संगठन में और अधिक कार्यकुशलता लाने के लिये अनेक परिवर्तन किये गये हैं ।

(ख) परिवर्तन संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध किन्हीं विशिष्ट आरोपों के आधार पर नहीं किये गये हैं ।

श्री कमला मिश्र "मधुकर" : अध्यक्ष जी, हम लोगों की जानकारी है कि जिन राज्यों में ग्रान्ड एलाएन्स की पार्टियां और खास कर सम्पूर्ण क्रान्ति की पार्टियां हुकूमत में थी, इन लोगों ने न केवल शासन के विभिन्न यन्त्रों, बल्कि पुलिस अधिकारियों को भी अपने प्रभाव में लाने का प्रयत्न किया है । सम्पूर्ण क्रान्ति के चक्कर में उन लोगों को भी शामिल किया है । बिहार के सम्बन्ध में मैं जानता हूं, यद्यपि वहां पर आपकी सरकार थी, उसके बावजूद भी आनन्द मार्ग और दूसरे किस्म के लोग . . .

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न तामिलनाडु के बारे में है, आप उसी पर प्रश्न पूछिये ।

श्री कमला मिश्र "मधुकर" : क्या आपको जानकारी है कि तमिलनाडु पुलिस में ऐसे पुलिस अधिकारी भी रहे हैं जो डी० एम० के० की पृथकतावादी नीतियों को प्रश्रय देते रहे है ? जब वहां डी० एम० के० की सरकार थी बिहार और दूसरे राज्यों से ऐसे लोग वहां गये थे जो सम्पूर्ण क्रान्ति के समर्थक थे और वहां की सरकार ने उनको प्रश्रय दिया, उनकी मदद की, जिसकी वजह से आपको यह हेरफेर करनी पड़ी ?

SHRI F. H. MOHSIN: Most of these transfers were effected because an impression was created that the local police officers had developed certain vested interests and had links with the local politicians. Also, because some